www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 128 | जौनपुर सोमवार, 22 दिसम्बर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

कर्नाटक में नफरती भाषण पर होगी 7 साल तक की सजा

बेंगलुरु , (एजेंसी)। कर्नाटक में नफरती भाषण पर अब सात साल तक की सजा हो सकती है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच विधानसभा के बाद राज्य विधान परिषद ने भी शुक्रवार को इसे मंजूरी दे दी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। इस कानून के तहत किसी संगठन या संस्थान द्वारा अपराध किए जाने पर हर व्यक्ति जो, अपराध के समय जिम्मेदार होगा उसे दोषी माना जाएगा। आरोपितों को साबित करना होगा कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती। नफरती भाषण के खिलाफ विधेयक पारित करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। भाजपा ने इसे विपक्ष के खिलाफ श्ब्रह्मास्त्रश और क्रूर करार दिया है।जमानत मिलना बेहद कठिन कार्यकारी मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उप पुलिस अधीक्षकों को अधिकार दिया गया है कि यदि उन्हें आशंका होगी कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई व्यक्ति या समूह इस कानून के तहत अपराध करेगा तो वे षनिवारक कार्रवाईष कर सकेंगे। प्रस्तावित कानून के तहत नफरती भाषण के मामले में जमानत मिलना बेहद कठिन होगा। विरोध के बीच यह विधेयक पारित कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कर्नाटक नफरती भाषण और नफरती अपराध (रोकथाम) विधेयक को विधान परिषद में पेश किया।

हरियाणा विधानसभा में वंदे मातरम् पर जमकर हंगामा

चंडीगढ, (एजेंसी)। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद हालात इतने बिगड़े कि कांग्रेस के विधायक विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के आसन के सामने पहुंच गए। बार–बार चेतावनी के बावजूद सीटों पर नहीं लौटने पर अध्यक्ष ने कांग्रेस के 10 विधायकों को सदन से 'नेम' कर बाहर करने के आदेश दे दिए। मार्शलों द्वारा बाहर ले जाने की कोशिश में हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। पूरे घटनाक्रम के कारण सदन की कार्यवाही करीब आधे घंटे तक स्थगित रही।यह विवाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन तब शुरू हुआ, जब भाजपा विधायक घनश्याम दास और योगेंद्र सिंह राणा ने शून्यकाल के बाद संसद की तर्ज पर सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल और अन्य कांग्रेस विधायकों ने इसके औचित्य पर सवाल उठाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति दे दी। कांग्रेस की ओर से आदित्य सुरजेवाला ने चर्चा की शुरुआत करते हुए वंदे मातरम् की भावना को पर्यावरण से जोड़ते हुए प्रदूषण, नदियों और जंगलों की स्थिति पर सवाल खड़े किए।

पीएम मोदी देंगे करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल और असम का दौरा शुरू करेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों को करोड़ों की सौगात देंगे। शनिवार दोपहर बाद वे बंगाल से असम के लिए रवाना होंगे। दोनों ही राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों राज्यों के लिए खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह करीब 11रू15 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 3,200 करोड़ रुपये की लागत वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह नादिया जिले में एनएच–34 के बराजागुली–कृष्णनगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे फोर–लेन कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह उत्तर 24 परगना जिले में एनएच–34 के

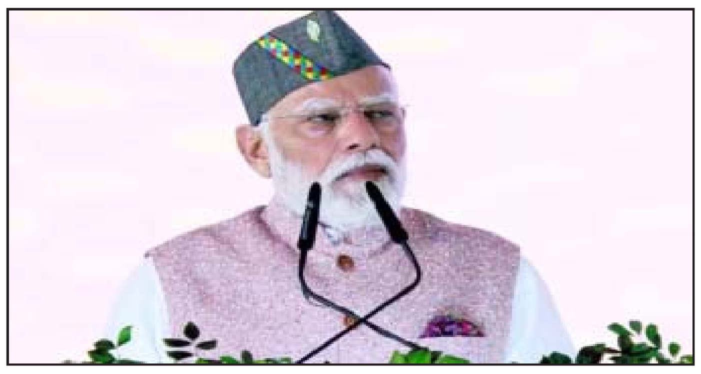

बरासातदृबराजागुली सेक्शन के 17. 6 किलोमीटर लंबे फोर–लेन कार्य की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट काफी अहम हैं। इनके शुरू होने से कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच रोड लिंक मजबूत हो सकेगा और सफर का समय करीब दो घंटे कम हो सकेगा। बिहार में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली बंगाल यात्रा है। प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि बंगाल में भी राजनीतिक बदलाव होगा। प्रधानमंत्री की रैली ताहेरपुर इलाके में आयोजित होगी। यहां मतुआ समुदाय और शरणार्थी आबादी की संख्या काफी अधिक है। यहां से चुनाव प्रचार शुरू करना केवल एक संयोग नहीं है। नादिया जिले का राणाघाट और उत्तर 24 परगना का ठाकुरनगर मतुआ समुदाय के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। भाजपा इस वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री एक रैली से कई जिलों को साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय असम यात्रा के दौरान 1600 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात पूर्वोत्तर राज्य को देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

विदेश में राष्ट्रहित के खिलाफ भारत विरोधी ताकतों से कर रहे गठजोड़ : गौरव भाटिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने शनिवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान ष्भारत को बदनाम करनेष का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांधी विदेशों में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाटिया ने कहा कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करना, भारत विरोधी ताकतों से मिलना, ये सब लोकसभा में भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। यह बेहद चिंताजनक है और भारतीय नागरिक भी इससे आक्रोशित हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी अक्सर संसदीय सत्रों के दौरान विदेश यात्रा करते हैं, जिसका उदाहरण उन्होंने हाल ही में जर्मनी की अपनी यात्रा से दिया। भाटिया ने कहा कि विपक्ष के नेता, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सत्र के दौरान संसद में उपस्थित रहना है,

लेकिन वे विदेश चले गए, जहां उन्होंने हर्टी स्कूल में जाकर प्रोफेसर डॉ. कॉर्नेलिया वोल से मुलाकात की। इससे उनके एजेंडे और इरादों पर सवाल उठते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस (एक निवेशक और परोपकारी व्यक्ति, जिन पर अक्सर दक्षिणपंथी लोग निशाना साधते हैं) के बीच संबंध हैं। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए कहा कि इन संस्थाओं का भारत विरोधी गतिविधियों से संबंध है। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस दो शरीर, एक आत्मा (दो जिस्म, एक जान) की तरह हैं, और अब एक और सबूत सामने आया है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं।

इस बार छुट्टी के दिन बजट पेश कर सकती हैं निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अगर संसदीय परंपराओं का पालन किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2026–27 का आम बजट रविवार के दिन पेश कर सकती हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह संभावना जताई। दरअसल, वर्ष 2017 से बजट एक फरवरी को पेश किया जाता रहा है और अगले वर्ष इस दिन रविवार

है। संसद की बैठकें खास परिस्थितियों में रविवार को भी होने के उदाहरण हैं। 2020 में कोविड–19 महामारी के दौरान और 13 मई, 2012 को संसद की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रविवार के दिन बैठकें आयोजित की गईं। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये फैसले संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति उचित समय पर लेती है। गौरतलब है कि मोदी सरकार में बजट पेश करने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की गई, ताकि एक अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बजट को लागू किया जा सके। एक अधिकारी के अनुसार, आम बजट प्रस्तुत करने के लिए हमने तारीख तय कर रखी है। रविवार की अवधारणा तो अंग्रेजों द्वारा लाई गई है। साल 2017 से पहले आम बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से की मुलाकात

गोरखपुर, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाय। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। सीएम

योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा। जनता दर्शन में आई एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी किए जाने का मामला मुख्यमंत्री को बताया। इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित का पैसा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला को भी समझाते हुए कहा, विदेश जाने के नाम पर एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गलत तरीके से जाने पर लोगों को वहां जेल में रहना पड़ जाता है। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे।

मजबूत होगी जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश के बंदरगाहों और जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार एक वैधानिक निकाय ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (बीओपीएस) की स्थापना करेगी। यह निकाय बंदरगाहों और पोतों से जुड़ी सुरक्षा सूचनाओं का समय पर विश्लेषण, संग्रह और आदान–प्रदान सुनिश्चित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बीओपीएस के गठन को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल तथा नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में देशव्यापी, मजबूत और समन्वित पोर्ट सुरक्षा ढांचा तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया गया। अमित शाह ने निर्देश दिया कि सुरक्षा उपायों को चरणबद्ध और जोखिम–आधारित तरीके से लागू किया जाए। इसमें बंदरगाहों की

संवेदनशीलता, व्यापारिक क्षमता, भौगोलिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में यह भी कहा गया कि समुद्री सुरक्षा ढांचे से मिले अनुभवों को विमानन सुरक्षा क्षेत्र में भी अपनाया जाएगा। बीओपीएस का गठन नए मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जाएगा। यह निकाय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की तर्ज पर होगा और बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। इसका नेतृत्व एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे, जो इसके महानिदेशक होंगे। संक्रमणकाल के एक वर्ष के दौरान, महानिदेशक (शिपिंग) ही बीओपीएस के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीओपीएस जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से जुड़े नियामक और पर्यवेक्षण कार्यों की जिम्मेदारी निभाएगा। इसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और डिजिटल खतरों से पोर्ट आईटी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को मान्यता प्राप्त सुरक्षा संगठन घोषित किया है, जो बंदरगाह सुविधाओं के लिए सुरक्षा आकलन और सुरक्षा योजनाओं की तैयारी करेगा। इसके साथ ही, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण देगा ।

कोडिन कफ सिरप कांड के दोषी को उल्टा लटका देंगे : सीएम केशव मौर्य

लखनऊ, (संवाददाता)। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर शनिवार को फिर निशाना साधा। उन्होंने से बातचीत में कहा, समाजवादी पार्टी और माफिया एक–दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कोडिन कफ सिरप के पीछे जो भी दोषी होगा, उसे उल्टा लटका दिया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस और की जांच चल रही है। अखिलेश यादव किसी को नहीं बचा सकते। वहीं, के बारे में अखिलेश यादव के ट्वीट पर, उन्होंने कहा, जब से वह (अखिलेश यादव) बिहार में हारने के बाद वापस आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अगर हम उनके ट्वीट को देखें, तो वह के संबंध में हर दिन नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और नए मुद्दे उठाते हैं। लेकिन, बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके लिए चुनाव

आयोग को धन्यवाद देते हैं। कार्यकर्ता हर बूथ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन, उनके (समाजवादी पार्टी) पास कार्यकर्ता नहीं हैं और सिर्फ गुंडे, अपराधी और माफिया हैं।

असम में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत, ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे

मालिगांव, (एजेंसी)। असम के जमुनामुख–कामपुर खंड में शनिवार तड़के एक बड़ा रेल हादसा टल गया। लुमडिंग मंडल के जामुनामुख–कंपूर सेक्शन में ट्रेन संख्या 20507 डाउन सैरांग–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिसके कारण ट्रेन का इंजन और पांच कोच पटरी से उतर गए ।यह हादसा सुबह करीब 2रू17 बजे हुआ। हालांकि, राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई और न ही किसी तरह की जनहानि हुई। यह क्षेत्र गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर है। घटना की जानकारी मिलते ही दुर्घटना राहत ट्रेनें और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच

गए ।जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 7 हाथियों की मौत हो गई और हाथी का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर 0361–2731621, 2731622 और 2731623 जारी किए गए ताकि यात्री और उनके परिजन संपर्क कर सकें ।पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, लुमडिंग मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं। प्रभावित कोचों के यात्रियों को फिलहाल दूसरे डिब्बों में खाली बर्थों पर शिफ्ट किया गया। ट्रेन से क्षतिग्रस्त कोचों को अलग किया गया और सुबह 06रू11 बजे ट्रेन गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। गुवाहाटी पहुंचने के बाद ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे और उसके बाद ट्रेन अपनी आगे की यात्रा जारी करेगी ।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह हादसा उस जगह पर हुआ, जो निर्धारित हाथी कॉरिडोर नहीं है। लोको पायलट ने हाथियों का झुंड देखने पर आपातकालीन ब्रेक लगाए।

जब खुद फंस जाओ, तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ : अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, जो घटनाक्रम चल रहा है कोडिन को लेकर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सरकार छिपा रही है। 36 जिलों में 118 से अधिक थ्प्त और यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार चल रहा था। कई तस्वीरें दिखाई जा रही है, तो अगर हम तस्वीरों को ही ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही माफिया है। तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री के साथ भी है। मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम के साथ भी है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक फैला अवैध कारोबार

अखिलेश यादव ने कहा, कोडीन कफ सिरप का अवैध कारोबार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक फैला

हुआ है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये में है। मुख्यमंत्री और उनके साथ खड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर सरकार सच में माफियाओं के खिलाफ है, तो जिन–जिन लोगों की तस्वीरें मेरे साथ दिखाई जा रही हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। चाहे 'कालीन भैया' हों या 'कोडीन भैया', इस अवैध धंधे में शामिल हर व्यक्ति पर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर अपनी बात न रख सकें, इसके लिए पूरी पुलिस से सिटी बजवाई जाती है। पूर्व विधायक दीपक यादव को फर्जी मामले में जेल भेजा गया। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर शायराना अंदाज में कहा था कि जब खुद फंस जाओ, तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। सपा अध्यक्ष आगे दोनों डिप्टी सीएम और सीएम का फोटो लगाते हुए कहते हैं ...फुल दो हॉफ हैं, यूं तो आपस में खिलाफ हैं। कोडीन के मारे ये सारे, आज डर के मारे साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि नशाखोरी की जांच के लिए सिरप टॉस्क फोर्स मतलब एसटीएफ के साथ–साथ जीटीएफ भी बना दीजिए। बाकी जनता समझदार है। भाजपाइयों के चेहरों पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। कोडीन कफ सिरप की सच्चाई वे जानते हैं, तभी खुद नहीं पी, इसीलिए बीच में किसी को खांसी भी आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि अवैध और जहरीली कफ सिरप मामले की जांच कर रही एसटीएफ भी अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

संपादकीय

बढ़ रही बेरोजगारी

खबरों के मुताबिक सरकार इस आकलन पर है कि पूंजी केंद्रित उद्योग पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहे, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए अब श्रम केंद्रित कारोबार में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। मगर मुद्दा है कि यह निवेश कौन करेगा? खबरों के मुताबिक श्रम केंद्रित कारोबार को खड़ा करना अब केंद्र की प्राथमिकता है। इसके लिए अगले बजट में खास प्रावधान किए जाएंगे। इस सोच के पीछे यह आकलन है कि पूंजी केंद्रित उद्योग पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसलिए अब श्रम केंद्रित कारोबार में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। मगर मुद्दा है कि यह निवेश कौन करेगा? क्या औपचारिक क्षेत्र को श्रम केंद्रित उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? जब औपचारिक क्षेत्र में भी निजी निवेश की स्थिति कमजोर बनी हुई है, तो वित्तीय कारोबार में अधिक मुनाफा देखने वाले पूंजीपतियों को प्राथमिकता बदलने के लिए कैसे राजी किया जा सकेगा? तो निगाहें सूक्ष्म, लघु और मझौले दर्जे के ये उद्योगों (एमएसएमई) पर टिकती है। ये उद्योग श्रम केंद्रित उत्पादन करते हैं। अनुमानतरू देश में इनकी संख्या सवा सात करोड़ से ज्यादा है। मगर बजट में इनके लिए क्या किया जा सकता है? अधिक से अधिक सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा हो सकती है। या टैक्स संबंधी रियायतें दी जा सकती हैं। इसके बावजूद बाजार मिलने का सवाल बना रह जाएगा। उत्पाद के लिए बाजार मौजूद नहीं हो, तो कोई कारोबारी ऋण लेकर निवेश के लिए प्रेरित नहीं होता। और इस क्षेत्र को बाजार तक तब नहीं मिल सकता, जब तक उसे चीन के सस्ते सामानों से संरक्षण नहीं मिलता। श्रम केंद्रित इस सेक्टर की बदहाली में यह एक बड़ा पहलू रहा है, हालांकि नोटबंदी और उलझाऊ जीएसटी ने भी उसके लिए कम समस्याएं खड़ी नहीं कीं। खबरों के मुताबिक सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश बढ़ा कर रोजगार उन्मुख रास्ते पर आगे बढ़ेगी। मगर क्या सचमुच मौजूदा सरकार में इन क्षेत्रों को मुनाफा केंद्रित कारोबारियों से वापस सार्वजनिक क्षेत्र में लाने की इच्छाशक्ति है? अगर हां, तो उसे इस संबंध में व्यापाक नीति परिवर्तन का एलान करना चाहिए। बजट ऐसा करने का जरिया नहीं है। वह अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने का माध्यम नहीं है। हां, बजट को निराधार नैरेटिव गढ़ने का मौका जरूर बनाया जा सकता है, जिसमें वर्तमान सरकार को महारत हासिल है।

भारत के हलाल सर्टिफिकेशन को ओमन की मंजूरी

नीरज

देश–विदेश में वर्षों से हलाल सर्टिफिकेशन एक संगठित धंधा बन चुका है। कुछ निजी संस्थाएँ खुद को 'धर्म का ठेकेदार' घोषित कर मोटी फीस के बदले हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं वह भी बिना किसी सरकारी निगरानी, बिना पारदर्शिता और बिना जवाबदेही के। इन्हीं संस्थाओं को लेकर बार–बार यह गंभीर सवाल उठते रहे हैं कि उनके पास इकट्ठा हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है। जाँच एजेंसियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी आगाह किया है कि जब पैसा बिना नियंत्रण के बहे, तो वह टैरर फंडिंग जैसे खतरनाक रास्तों पर भी जा सकता है। समस्या यह थी कि मुस्लिम देशों में खासकर खाड़ी बाजारों में, हलाल प्रमाणन के बिना भारतीय मांस और खाद्य उत्पाद बेचना लगभग नामुमकिन था। इस मजबूरी का फायदा उठाकर वही निजी संगठन निर्यातकों की गर्दन पर सवार रहे। सर्टिफिकेट चाहिए तो उनकी शर्तें मानो, उनकी कीमत दो, उनकी व्यवस्था स्वीकार करो, चाहे वह कितनी ही अपारदर्शी क्यों न हो। सरकार की गैरमौजूदगी में यह समानांतर सत्ता वर्षों तक फलती–फूलती रही। लेकिन अब इस खेल पर ब्रेक लगने लगा है। भारत सरकार ने आधिकारिक, सरकार–मान्य और अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हलाल प्रमाणन को लागू कर उस पूरे नेटवर्क की जड़ पर चोट की है, जो आस्था की आड़ में कारोबार और संभावित रूप से आतंकी फंडिंग का रास्ता खोलता रहा। ओमान द्वारा भारत के सरकारी हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता दिया जाना सिर्फ निर्यातकों के लिए राहत नहीं है, यह उस अनियंत्रित सिस्टम के खिलाफ सीधी कार्रवाई है, जिसे अब तक कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह कदम साफ संदेश देता है कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन आस्था के नाम पर लूट, दलाली और संदिग्ध फंडिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपको बता दें कि भारत ने अपने निर्यात हितों को साधने और वैश्विक बाजार में धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप व्यापार को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत उन सभी देशों से मिशन मोड में संवाद कर रहा है, जहाँ मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल प्रमाणन अनिवार्य है। इस कड़ी में ओमान के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित भारतदृओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (ब्न्च।) एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ है। पीयूष गोयल ने बताया है कि ओमान पहला ऐसा देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से भारत के हलाल मांस प्रमाणन को मान्यता दी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले खाड़ी देशों और अन्य इस्लामिक देशों में हलाल प्रमाणन के नाम पर अनौपचारिक और अपारदर्शी प्रक्रियाएँ चल रही थीं। भारत पिछले तीनदृचार वर्षों से प्रयास कर रहा था कि इन देशों को औपचारिक और सरकार स्वीकृत हलाल प्रमाणन प्रणाली अपनाने के लिए राजी किया जाए। इस समझौते के तहत ओमान भारत के हलाल प्रमाणन को सीधे स्वीकार करेगा, जिससे दोहराव वाली जाँच, अतिरिक्त प्रमाणन और अनावश्यक लागत से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। इससे न केवल निर्यात लागत घटेगी, बल्कि भारतीय उत्पादों की बाजार तक पहुँच भी तेज और आसान होगी। पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब सभी 55 इस्लामिक देशों के साथ इसी तरह की व्यवस्था लागू कराने के लिए सक्रिय बातचीत करेगा। देखा जाये तो भारत ने अब साफ कर दिया है कि धार्मिक मान्यताओं का सम्मान होगा, लेकिन अव्यवस्था और दलाली की कीमत पर नहीं। औपचारिक और प्रक्रिया आधारित हलाल प्रमाणन की बात दरअसल भारत के उस इरादे का संकेत है, जिसमें वह आस्था को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जोड़ना चाहता है। यह उन तमाम आलोचकों के लिए भी जवाब है, जो हलाल को लेकर या तो अंध–विरोध करते हैं या फिर आंख मूंदकर उसका समर्थन करते हैं।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो खाड़ी और इस्लामिक देश भारत के लिए कोई मामूली बाजार नहीं हैं। मांस, खाद्य प्रसंस्करण और ऑर्गेनिक उत्पादों में ये देश बड़े आयातक हैं। यदि भारत अपने प्रमाणन को इन बाजारों में मान्य करा लेता है, तो यह सिर्फ निर्यात बढ़ाने का मामला नहीं होगा, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की साख मजबूत करने का मामला होगा। सबसे अहम बात यह है कि यह पहल भारत को 'रिएक्टिव' से 'प्रोएक्टिव' बना रही है। अब भारत दूसरों के बनाए नियमों को चुपचाप स्वीकार करने वाला देश नहीं, बल्कि अपने मानकों को आत्मविश्वास से पेश करने वाला खिलाड़ी बन रहा है। हलाल प्रमाणन का यह कदम दरअसल एक बड़े संदेश का हिस्सा है यानि भारत अब वैश्विक व्यापार में बराबरी से बात करेगा, न झुकेगा, न हिचकेगा। बहरहाल, असली परीक्षा तब होगी जब भारत बाकी 54 इस्लामिक देशों में भी इसी तरह की औपचारिक मान्यता हासिल करेगा। तब यह कहा जा सकेगा कि भारत ने न सिर्फ व्यापार जीता, बल्कि व्यवस्था भी।

सेकुलरवाद का बहाना, वोटरों पर निशाना

उमेश

बिहार में जाति–धर्म की सियासी पिच पर बुरी तरह मात खाने के बावजूद इंडिया गठबंधन का भरोसा इसी पर है। तमिलनाडु में जिस तरह कार्तिगई दीपम परंपरा स्थापित करने का आदेश देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ गठबंधन ने लामबंदी की है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोई की अगुआई में विपक्षी गठबंधन के 120 सांसदों द्वारा स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गठबंधन की पारंपरिक राजनीति का ही विस्तार है। विपक्षी गठबंधन यह पचा नहीं पा रहा है कि कथित सेकुलर देश में किसी जज ने बहुसंख्यक सनातनी परंपरा स्थापित करने का निर्णय दे दिया है। स्वामीनाथन के फैसले के अनुसार, जहां कार्तिदीपम मनाया जाना है, वहां एक दरगाह भी है। दरगाह और मंदिर साथ हो तो मंदिर की कीमत पर दरगाह की परंपराएं अपने यहां चलती रही हैं। अब तक की शासन व्यवस्था के लिहाज से ऐसे मामलों में मंदिर के पक्ष में फैसला सवालों के घेरे में आता है। स्वामीनाथन ने मदुरै जिले की थिरूपरनकुंद्रम की पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम की परंपरा को स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिसे 1920 के एक विवाद के बंद कर दिया गया था। यह बात और है कि डीएमके की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने विवाद की आशंका के बहाने अदालत के फैसले को लागू ही नहीं होने दिया। दिलचस्प है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका विरोध भी नहीं किया, बल्कि सरकार ही खुद आगे बढ़कर विवाद की आशंका से भर उठी। राज्य सरकार ने स्वामीनाथन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। लेकिन इस फैसले के लिए स्वामीनाथन को पचा नहीं पा रही है। उसे लगता है कि अगर उसने जज को सबक नहीं सिखाया तो उसकी सेकुलरवाद के बुनियाद पर टिकी राजनीति में दरार पड़ सकती है। जज को सबक सिखाने और न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के डीएमके के इस कदम में सबसे हैरतनाक कदम है, अखिलेश यादव का बढ़–चढ़कर हिस्सा लेना। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पेश करते वक्त कनिमोई के साथ कांग्रेसी नेताओं और अखिलेश की मौजूदगी के संकेत गहरे हैं। दरअसल महागठबंधन के दल अल्पसंख्यक समुदाय को यह संकेत देने की कोशिश में हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उसके हितों के लिए किसी जज को भी सूली पर चढ़ा सकता है। महागठबंधन की कोशिश कुछ महीने बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की करीब छह फीसद अल्पसंख्यक आबादी को लुभाना भी है। वैसे देखा जाए तो राज्य की सात करोड़ 21 लाख की आबादी में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या महज 42 लाख तीस हजार ही है। ब्राह्मणवाद की बुनियाद पर उभरी डीएमके की राजनीति में अल्पसंख्यकवाद पिछड़ी जातियों को लुभाने का भी मंत्र रहा है। राज्य की अधिसंख्य पिछड़ी आबादी को भी लुभाने की इस बहाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कार्तिगई दीपम की परंपरा को रोकने में डीएमके को कोई हिचक नहीं हुई। इस पूरे मसले पर चर्चा से पहले जानना जरूरी है कि कार्तिगई दीपम त्योहार है क्या? दक्षिम के दीप पर्व के रूप में विख्यात कार्तिगई दीपम भगवान मुरूगन के सम्मान में तमिल महीने में दीप जलाने की परंपरा है। शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय तमिलनाडु में मुरूगन और सुब्रह्मण्यम के नाम से भी जाने जाते हैं। मदुरै जिले की जिस थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम मनाने का आदेश अदालत ने दिया, वह भगवान मुरूगन की छह पवित्र जगहों में से एक है। मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शिवजी स्वयं अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसी दीप स्तंभ की स्मृति स्वरूप उचिपिल्लायर मंदिर के पास प्राचीन दीपाथुन नामक स्तंभ के नजदीक महादीपक जलाया जाता है। थिरूपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर भी इसकी परंपरा रही। लेकिन बाद में वहां मंदिर के नजदीक ही एक दरगाह स्थापित हो गई। दरगाह के बाद सेकुलरवाद को बढ़ावा देना जरूरी था, लिहाजा दीपम की परंपरा अधिकारियों ने रोक दी। जिसे शुरू करने को लेकर अदालती हस्तक्षेप की मांग की गई। पहले मदुरै की जिला अदालत में मामला चला और बाद में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद पहाड़ी पर तीन दिसंबर को दीप जलाने श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने लगा। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राज्य की स्टालिन सरकार का कहना था कि इससे खून–खराबा हो सकता है। जबकि अल्पसंख्यकों की ओर से ऐसी कोई कोशिश या बयानबाजी भी नहीं हुई थी। बहरहाल, डीएमके सरकार के इस फैसले ने राज्य में पैर जमाने की कोशिश में बैठी बीजेपी को मुद्दा दे दिया। पार्टी का कहना है कि डीएमके सेक्युलरिज्म की बात करती तो है, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ हिंदू समुदाय ही रहता है। बीजेपी का आरोप है कि डीएमके ने कभी किसी गैर हिंदू परंपरा, दरगाह या आदि पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर राज्य के हिंदुओं ने कौन सी गलती की है कि उन्हें दीप जलाने के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। डीएमके की पूर्ववर्ती जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। उसका घोषित उद्देश्य एनी बेसेंट की अगुआई वाले होम रूल लीग आंदोलन का विरोध था। जस्टिस पार्टी का मानना था कि अगर होमरूल आंदोलन सफल हुआ तो तमिलनाडु में जारी ब्राह्मणवाद की वजह से ब्राह्मण अधिकारियों की तादाद बढ़ जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जस्टिस पार्टी की स्थापना ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए हुई थी। कालांतर में उसकी ब्राह्मणवाद विरोध की राजनीति बढ़ते–बढ़ते ब्राह्मण विरोध पर केंद्रित हो गई। बाद में उसके विरोध के दायरे में हिंदी और पूरी सनातन परंपरा समा गई। यही वजह है कि स्टालिन कुनबे को हिंदुत्व की कटु आलोचना से कभी परहेज नहीं रहता। अहर्निश हिंदी विरोध और अब कार्तिगई दीपम का विरोध इसी परंपरा का विस्तार है। विपक्षी गठबंधन को इन दिनों संविधान बचाने की बहुत चिंता है। 'संविधान खतरे में है' की आवाज बुलंद करने वाले विपक्षी गठबंधन के दलों की नजर में न्याय वही है, जो उनके नैरेटिव के हिसाब से हो, अन्यथा वह सेकुलरवाद का विरोध है। राममंदिर पर सर्वोच्च न्यायाल के फैसले को ये दल अब भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी कदाचार के आरोप में रायबरेली का निर्वाचन खारिज कर दिया था, तब न्यायपालिका की शक्तियां ही क्षीण कर दी गईं। मोहन कुमार मंगलम तो इससे भी दो कदम आगे बढ़ते हुए प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात करने लगे थे। पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव के एक बयान को लेकर भी विपक्षी गठबंधन नाराज हो गया था। शेखर ने कहा था, ष्ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिन्दुस्तान है। यहां रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कघनून तो बहुसंख्यक से ही चलता है। इसी अंदाज में स्वामीनाथन पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसने एक बार फिर डीएमके और इंडिया गठबंधन की सियासी रणनीति का चेहरा उजागर किया है। डीएमके ने सेक्युलरिज्म आधारित जो प्रशासनिक मॉडल बनाया है, उसके निशाने पर सिर्फ हिंदू हैं। भगवान मुरुगन की सदियों पुरानी परंपरा को रोकना उसी मॉडल की परिणति है। डीएमके की नीति अल्पसंख्यक समुदायों को खुश करना और हिंदू समुदाय के खिलाफ आक्रामक रहा है। राज्य में वक्फ की जमीनों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। चर्च का धन भी अछूता है। लेकिन हिंदू मंदिरों के कोष पर राज्य का नियंत्रण है। मंदिरों की जमीनें भी सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन अब राज्य का जनमत बदल रहा है। बीजेपी की कोशिश तमिल हिंदुत्व को उभारकर अपनी बुनियाद को मजबूत करना है।

राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर संबंधों को मजबूत कर रहा भारत

एस. सुनील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ भारत के संबंधों को श्ध्रुव तारे की तरह अटलश्य बताया। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ही साझेदारी की नई बुनियाद रखी थी और उसके बाद दुनिया के कितने संकट देखे, दोनों देशों ने कितने उतार चढ़ाव देखे फिर भी दोनों के संबंधा स्थिर रहे। दोनों देशों ने अपने नागरिकों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के नए लक्ष्य तय किए। रूस समय की कसौटी पर आजमाया हुआ भारत का दोस्त है। उसे सही अर्थों में भारत का सदाबहार दोस्त कह सकते हैं। अनगिनत मौकों पर रूस का वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के काम आया है। 1971 की लड़ाई के समय अमेरिका के सातवें बेड़े के सामने रूस की समुद्री ताकत भारत के काम आई थी। रूस की तकनीक से भारत की सेना मजबूत और सक्षम हुई है तो रूसी तकनीक से भारत कुडनकुलम में सबसे सफल तरीके से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। रूसी तेल व गैस ने न सिर्फ भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित की। उसी रूस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की दोस्ती को एक नई ऊंचाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चार साल के बाद भारत की यात्रा पर आए तो जिस सहज अंदाज में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकातें हुईं और जितने मंचों पर दोनों ने अपनी बात रखी उससे कूटनीतिक, भू राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर दोनों की वैचारिक स्पष्टता और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की सोच सामने आई। दोनों के बीच भरोसा ऐसा दिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की गाड़ी शबीस्ट्य से चार गुना ज्यादा सुरक्षित राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी पीछे पीछे चली और वे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर प्राइवेट डिनर के लिए गए। दोपक्षीय संबंधों को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल सही कहा कि वे सिर्फ तेल और गैस की बात करने भारत नहीं आए हैं। यह बात उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश था, जो उनकी यात्रा से पहले अटकल लगा रहे थे कि रूस और भारत के बीच हजारों करोड़ रुपए के रक्षा सौदे होंगे या भारत तेल व गैस की खरीद का सौदा करेगा। यह कितनी बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा में कोई रक्षा सौदे होने की खबर नहीं आई। भारत एस 400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है या एस 500 भी खरीदेगा और एसयू 57 लड़ाकू विमान भी खरीदेगा। परंतु राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में इस बारे में कोई नया समझौता नहीं हुआ। पहले कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन अपना सामान बेचने भारत आ रहे हैं। परंतु इसका उलटा हुआ राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वे भारत से रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने को तैयार हैं। यानी उन्होंने भारत से आयात बढ़ाने की सैद्धांतिक सहमति दी। रूस के साथ अगर भारत का आयात बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत के औद्योगिक और विनिर्माण सेक्टर में तेजी आएगी। ध्यान रहे अभी तक ज्यादातर देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में चलता है। अमेरिका एक बड़ा अपवाद है, जिससे भारत जितना सामान खरीदता है उससे दोगुने से ज्यादा बेचता है। हालांकि अब टैरिफ बढ़ने से अमेरिका को होने वाला आयात भी कम हुआ है और उसके बाद ही भारत अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए दूसरे बाजार तलाश रहा था। अब रूस का बड़ा बाजार भारत को मिलने की गारंटी हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में जिन अनेक विषयों पर सहमति बनी है उसमें एक विषय अपनी मुद्रा में कारोबार करने की भी है। ध्यान रहे डॉलर की बढ़ती कीमत के कारण भारत का आयात बिल बढ़ रहा है। डॉलर के लिए भारत को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। रूस के साथ रुपए में कारोबार होने से भारत के आयात बिल में बड़ा अंतर आएगा, जिससे व्यापार घाटा कम होगा। ऐसे ही दुनिया के अनेक पश्चिमी देश और पूर्व में भी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीयों के प्रति घृणा अपराध में बढ़ोतरी हुई है और इन देशों ने वीजा के नियम भी सख्त किए हैं ताकि भारतीय छात्रों और पेशेवरों को आने से रोका जा सके। रूस के साथ समझौते के बाद भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए रूस में नए अवसर बनेंगे। भारत और रूस के बीच हुए 23वें सालाना शिखर सम्मेलन में इस पर सहमति बनी है कि रूस में भारत के कुशल पेशेवरों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए भारत और रूस के बीच स्किल्ड लेबर मोबिलिटी की संधि हुई है। इसी तरह से रूस भारतीय छात्रों के लिए भी अपने नियमों में ढील देगा। भारत भी रूस के नागरिकों को 30 दिन का मुफ्त वीजा देगा। यह भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के काम आने वाला निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ भारत के संबंधों को श्ध्रुव तारे की तरह अटलश्य बताया। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले राष्ट्रपति पुतिन ने ही साझेदारी की नई बुनियाद रखी थी और उसके बाद दुनिया के कितने संकट देखे, दोनों देशों ने कितने उतार चढ़ाव देखे फिर भी दोनों के संबंधा स्थिर रहे। दोनों देशों ने अपने नागरिकों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के साथ साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के नए लक्ष्य तय किए। दोनों देशों के बीच दोपक्षीय कारोबार को 2030 तक एक सौ अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभी 64 अरब डॉलर सालाना पर है।

बढ़ता उत्पादन, घटता खर्च, पर्यावरण की रक्षा

कोमल

आज हमारे किसानों के सामने तेजी से बढ़ते खर्च और कर्ज की परेशानी है। रासायनिक खाद से उत्पादकता अपेक्षा के अनुकूल बढ़ नहीं रही है जिसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके अत्यधिक उपयोग से पहले ही मिट्टी व पर्यावरण की बहुत क्षति हो चुकी है। कई स्तरों पर खेती व गांव का बिगड़ता पर्यावरण किसानों की इन समस्याओं को और बढ़ा रहा है। आखिर कोई तो बात होगी कि इस दलित किसान की खेती को आसपास के कई किसान देखने–समझने आते हैं व सरकारी स्तर पर उन्हें पुरस्कार भी दिया गया है व प्रशिक्षण देने के लिए भी बुलाया जाता है। जब यह लेखक टीकमगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) के लिधोराताल गांव में बालचंद अहीरवार से बातचीत करने पहुंचा तो यह समझने में देरी नहीं लगी कि इस मेहनती, निष्ठावान किसान की खेती किसानों व अधिकारियों को क्यों आकर्षित कर रही है।आज हमारे किसानों के सामने तेजी से बढ़ते खर्च और कर्ज की परेशानी है। रासायनिक खाद से उत्पादकता अपेक्षा के अनुकूल बढ़ नहीं रही है जिसका एक बड़ा कारण यह है कि इसके अत्यधिक उपयोग से पहले ही मिट्टी व पर्यावरण की बहुत क्षति हो चुकी है। कई स्तरों पर खेती व गांव का बिगड़ता पर्यावरण किसानों की इन समस्याओं को और बढ़ा रहा है। बालचंद, उनकी पत्नी गुड्डी और परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से जो खेती अपने मात्र 2 एकड़ के खेत पर कर रहे हैं, उसकी बड़ी उपलब्धि यह है कि किसान संकट उत्पन्न करने वाली इन सभी समस्याओं का समाधान उनकी खेती में एक साथ नजर आ रहा है। अपने छोटे खेत व उससे जुड़े कार्यों के बल पर ही बालचंद और गुड्डी परिवार को बहुत स्वस्थ खाद्य खिला रहे हैं व अपने दोनों बेटों को शहर के कालेज में पढ़ा रहे हैं।इनकी मेहनत और रचनात्मकता की प्रशंसा करनी होगी कि मात्र 2 एकड़ के खेत में एक वर्ष में 44 तरह के खाद्य उगाते हैं जिनमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, फल, फूल सब्जी सभी कुछ है। बहुत से फलदार व अन्य पेड़ भी हैं। मुख्य फसल गेंहू व मूंगफली है। इसके साथ कुछ स्थान पर वे बहुस्तरीय बगीचा लगते हैं जिसमें जमीन के नीचे, छोटे व बड़े पौधों पर, बांस तथा रस्सी पर बढ़ रही बेलों पर बहुत सी सब्जियां लगाते हैं। वर्ष भर पौष्टिक खाद्य मिलते रहते हैं व बिक्री के लिए भी कुछ न कुछ निकलता रहता है।यह सभी कार्य प्राकृतिक खेती पद्धति से किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा व खरपतवारनाशक दवा आदि का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर अपने ही खेत में गोमूत्र, गोबर व स्थानीय पेड़ों की कड़वी पत्तियों आदि से हानिकारक कीड़ों को दूर रखने वाली दवा तैयार की जाती है। इस तरह बालचंद ने एक एकड़ में खेती का खर्च 6000 रुपए से कम कर 500 रुपए कर लिया है। वह बताते हैं कि हम छोटे किसान हैं, हमें ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, हमारा काम तो पावर ट्रिलर से हो जाता है जो मिट्टी के लिए भी अच्छा है। इन तौर–तरीकों से मिट्टी सुधर रही है व उपजाऊपन बढ़ रहा है। बालचंद ने मिट्टी खोदकर दिखाया कि अब इसमें कितने केंचुए आ गए हैं जो निरंतर अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से मिट्टी का उपजाऊ और भुरभुरा बनाए रखते हैं।बालचंद और गुड्डी ने एक कदम आगे चलकर सोचा कि हम अन्य किसानों के लिए भी यह राह क्यों न आसान करें? अतरू सृजन संस्था से सहायता प्राप्त कर उन्होंने एक ऐसा प्राकृतिक कृषि केन्द्र अपने खेत पर ही स्थापित किया जिससे वे अपनी जरूरत के अतिरिक्त भी प्राकृतिक खाद व हानिकारक कीड़े दूर रखने की दवा तैयार कर सकते हैं ताकि अन्य पड़ोस के किसान (जो किसी कारण से यह स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं) वे अपेक्षाकृत कम कीमत पर यह उनसे खरीद सकें। इसके अतिरिक्त बालचंद को प्राकृतिक कृषि के प्रशिक्षक के रूप में भी आमंत्रित किया जाता है व इस अवसर का भरपूर उपयोग कर वे प्राकृतिक खेती का संदेश फैलाते हैं।वे दो संदेश विशेष तौर पर पहुंचाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जिस तरह की प्राकृतिक व दर्जनों उपज वाली मिश्रित खेती वे कर रहे हैं, वह बहुत मेहनत और निष्ठा से ही हो सकती है। यदि मेहनत और खेती के प्रतिनिष्ठा नहीं है, वहां सफलता मिलनी कठिन है। साथ में वे समझते हैं

कि ऐसी रचनात्मक मेहनत थकाती नहीं है अपितु प्रसन्न रखती है क्योंकि आप निरंतर कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बालचंद व गुड्डी ने यह समझाई कि किसान के लिए नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि सारा हिसाब–किताब बिगड़ जाएगा यदि रोज–रोज मेहनत का पैसा शराब, तंबाकू व अन्य तरह के नशे में जाने लगे। अतरू बालचंद अपने को हर तरह के नशे से दूर रखते हैं। इस तरह के अनेक अन्य छोटे किसान भी प्राकृतिक खेती की राह चलते हुए बड़ी उम्मीद जगा रहे हैं। इसी तरह के एक–एक किसान हैं भील आदिवासी किसान मालीराम व उनकी पत्नी दुलकी बाई। जब यह लेखक प्रतापगढ़ जिले (राजस्थान) के उनके गांव कटारों का खेड़ा में गया तो मालीराम जी को अपने पौधों और पेड़ों के बीच में बहुत मस्त पाया। उन्होंने बताया कि वे अपने तीन बीघे के खेत में प्राकृतिक खेती पद्धति से 15 तरह की सब्जियों सहित लगभग 25 तरह की फसल उगाते हैं व इसके अतिरिक्त उनके खेत में अमरूद, पपीते, आंवले, नींबू, कटहल, चंदन आदि के लगभग 200 पेड़ हैं। उनके पास गाय, बैल, बकरियां व मुर्गियां हैं। खेती बैलों से होती है। इन पशु–पक्षियों से पर्याप्त व अच्छी गुणवत्ता की खाद प्राप्त होती है। पूरे खेत का नियोजन इस तरह है कि कुछ भी व्यर्थ न हो। यहां का अवशेष वहां पर संसाधन के रूप में उपयोग हो जाता है। मालीराम अपनी खेती में इतने मग्न हैं कि वह बाहर से आए मित्र को एक–एक क्यारी व पौधा दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या प्रयोग किया व उसका कितना अच्छा परिणाम उन्हें मिला।अमेरिकी किसान व दार्शनिक वैंडल बेरी ने लिखा है कि अच्छा किसान वह है जो आराम करते समय भी खेती को बेहतर करने के बारे में सोचता है। मालीराम से बातचीत करते हुए मुझे अनायास ही बैरी के इस कथन की याद आई क्योंकि बैरी के अनुरूप ही किसान मेरे सामने था। मालीराम ने बताया कि पहले वे भी रासायनिक खाद के जाल में फंस गए थे, पर अपनी गलती का अहसास उन्हें शीघ्र ही हो गया और वे उससे पीछे हट गए। उन्होंने अपने तीन बीघा के खेत को एक–एक बीघा कर तीन वर्षों में प्राकृतिक खाद से उपचारित किया ताकि इसकी मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन लौट सके। फिर उन्होंने अपने भाई को भी प्राकृतिक खेती के लिए कहा व उसने अब यह स्वीकार भी कर लिया है। शशि प्रजापति निवाड़ी जिले (मध्य प्रदेश) की ऐसी किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती सुधारने के साथ–साथ पूरे गांव की खेती सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके गांव कु दार में पुरनिया तालाब की सफाई कर इसकी मिट्टी–गाद से खेतों का उपजाऊपन बढ़ाया गया। इस पूरे प्रयास से गांववासियों को जोड़ने व इसकी प्रगति का रिकार्ड रखने में शशि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रदेश में जल्द बढ़ सकता है शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बेसिक शिक्षा ने सदन में दिया यह बयान

लखनऊ, (संवाददाता)। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा कि शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर जल्द ही सरकार निर्णय लेगी। इस निर्णय से यथासमय सदन को भी अवगत कराएंगे। यह मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्न प्रहर में उठाया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि किसी कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। कि उन्हें कैशलेस इलाज के लिए 89 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है। जल्द ही इस सुविधा के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। शिक्षक दल के ध्रुव त्रिपाठी ने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को जीपीएफ भुगतान में आ रही दिक्कतों को सामने रखा। नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छह माह के अंदर नव सृजित जिलों में आ रही समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। सपा के लाल बिहारी यादव ने निजी शिक्षा बोर्ड के प्रचार–प्रसार में अधिकारियों के लगने का मुद्दा उठाया। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जांच कराएंगे। सपा सदस्य किरण पाल ने शामली मे नाले की समस्या को उठाया। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे। सपा के मुकुल यादव ने नगर पंचायत करहल में श्मशान न होने का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से जल्द श्मशान की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया गया। भाजपा के ही सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु में शिक्षक के पद पर रिश्वत लेकर अयोग्य लोगों के चयन और आरक्षण का पालन नहीं किए जाने की बात कही। नेता सदन ने कहा कि यह गंभीर मामला है। अगर आरक्षण की प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ होगा तो जांच कर कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा के ही रविशंकर श्पप्पू भैयाश ने जननायक चंद्रशेखर विवि, बलिया में जमीन दाता को कार्य परिषद में शामिल न किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सदन में ही लखीमपुर खीरी में भारत–नेपाल सीमा से नैमिष और ओरछा (मध्य प्रदेश) तक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मांग भी उठी। भाजपा के विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने चीनी माझे की समस्या को सदन में उठाया।

एलडीए के फ्लैट खरीदारों को राहत, अब तीन साल पीछे से नहीं देना होगा मेंटीनेंस शुल्क

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए की पुरानी योजनाओं के खाली पड़े फ्लैटों के खरीदारों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें कब्जा मिलने की तारीख से पहले का तीन साल पुराना मेंटेनेंस शुल्क नहीं देना होगा। इसको लेकर एलडीए ने आदेश भी पास कर दिया है। अभी तक एलडीए उन नए आवंटियों से भी तीन साल का पिछला मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा था, जिन्होंने हाल ही में फ्लैट खरीदा था। आवंटियों का तर्क था कि जब फ्लैट उनके नाम पर था ही नहीं, तो वे पुराने समय का शुल्क क्यों दें। इस पर एलडीए उस नियम का हवाला दे रहा था, जिसके तहत अपार्टमेंट का काम पूरा होने और पहली रजिस्ट्री होने की तारीख से ही सभी फ्लैटों पर तीन साल का मेंटेनेंस शुल्क लागू हो जाता था। इसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति की, जिसके बाद अब एलडीए ने अपना नियम बदला है। तीन साल का अतिरिक्त मेंटेनेंस शुल्क लेने से एक आवंटी पर करीब 50 से 60 हजार रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। एलडीए पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत फ्लैट बेच रहा है, जिसमें छूट भी दी जा रही है। ऐसे में जब आवंटी रजिस्ट्री कराकर कब्जा लेने जा रहे थे तो उनसे तीन साल पहले का शुल्क मांगा जा रहा था। एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नए खरीदारों के लिए मेंटेनेंस शुल्क लेने की व्यवस्था में बदलाव हुआ है। एलडीए बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें तीन साल पीछे का मेंटेनेंस शुल्क न लेने का प्रावधान है।

संक्षिप्त खबरें

चाइनीज मांझे के विरोध में उतरे कीलर मांझा प्रतिबंध अभियान समिति के लोग

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । यूपी के जौनपुर में प्रतिबंधित चाइनीजध्नायलॉनधसिंथेटिक मांझे के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 11 जुलाई 2017 को इस घातक मांझे पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आठ साल बाद भी यह जिले के बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। नायलॉन, प्लास्टिक, तात वाला, सीसा लेपित या कोई भी गैर–बायोडिग्रेडेबल मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि केवल सूती धागा ही सुरक्षित है। प्रशासन की कथित उदासीनता के कारण यह मांझा सड़कों पर जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में 11 दिसंबर को शास्त्री ब्रिज पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर लौट रहे 40 वर्षीय निजी स्कूल शिक्षक संदीप तिवारी प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आ गए। मांझे की तेज धार से उनकी गर्दन कट गई और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह कोई अकेली घटना नहीं हैय इस साल जौनपुर और प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा, पक्षी और जानवर भी इस घातक मांझे में फंसकर घायल हो रहे हैं। इस आक्रोश और चिंता से प्रेरित होकर ष्कीलर मांझा प्रतिबंध अभियान समितिष ने शुक्रवार से शहर में एक जोरदार पोस्टर अभियान शुरू किया है। लाल–पीले रंग के इन प्रभावशाली पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा है, ष्प्रतिबंधित मांझा– मौत का फंदाष और ष्नायलॉन धागाध्प्लास्टिक धागाधसिंथेटिक मांझा पूर्ण प्रतिबंधितष। पोस्टरों में घायल गले की तस्वीरें लोगों को इस खतरे के प्रति सचेत कर रही हैं। समिति के संयोजक और अधिवक्ता अतुल सिंह ने अपने साथियों आशीष शुक्ल, विराज ठाकुर, सुधांशु सिंह, डॉ. अब्बासी, दिव्यप्रकाश सिंह, अंकित यादव सहित अन्य के साथ सड़कों पर उतरकर चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक संदीप तिवारी जैसे निर्दोष व्यक्ति की मौत ने हमें मजबूर किया है कि अब जनता स्वयं जागरूक हो। समिति लोगों से अपील करती है कि प्रतिबंधित पतंग धागा न बेचें, न खरीदें और न ही उपयोग करें। केवल सूती धागे का उपयोग करके पतंगबाजी के आनंद को सुरक्षित बनाएं। प्रतिबंधित मांझे के उल्लंघन पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आईईटी के पूर्व विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में लहराया परचम

लखनऊ, (संवाददाता)। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के पूर्व

विद्यार्थियों ने संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में परचम लहराया है। संस्थान के मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के पांच पूर्व विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया स्तर पर 10वीं, 29वीं, 33वीं, 39 वीं व 85वीं रैंक प्राप्त की है। संस्थान के निदेशक प्रो. विनीत कंसल ने बताया कि संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2019 बैच के अमित सिंह ने ऑल इंडिया 10वीं रैंक पाई है। अमित सिंह वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग के 2021 बैच के पास आउट कार्तिकेय सिंह ने 29वीं रैंक प्राप्त की है। वर्तमान में वह एनपीसी आईएल के एटॉमिक एनर्जी विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर तैनात है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2021 बैच की पास आउट छात्रा अलका यादव ने 33वीं रैंक व सिविल इंजीनियरिंग के 2018 बैच के पास आउट छात्र शुभम शर्मा ने 39वीं प्राप्त की है। वे दिल्ली मेट्रो में मैनेजर के पद पर तैनात है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग के 2024 बैच के पास आउट छात्र मयंक राय ने 85वीं प्राप्त कर संस्थान को गौरवान्वित किया है।

'ओमेक्स ने एनुअल डे और लीडरशिप समिट 2025 का किया आयोजन'

'लखनऊ। देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनी ओमेक्स द्वारा एनुअल डे और लीडरशिप समिट 2025 में ओमैक्स लखनऊ की मजबूत और असरदार भागीदारी देखने को मिली। इस दो दिवसीय आयोजन में "टुगेदर फॉर टुमॉरो–एक साथ, एक सपना" थीम के तहत कंपनी के भविष्य के रोडमैप, तकनीक आधारित विकास और इसमें टियर 2 के शहरों की भूमिका पर खघस चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में ओमेक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रोहतास गोयल, प्रबंध निदेशक श्री मोहित गोयल, कार्यकारी निदेशक श्री जतिन गोयल और बिजनेस हेड अंजनी कुमार पाण्डेय मौजूद रहे। सत्रों के दौरान आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल, उपभोक्ताओं के बदलते व्यवहार और टियर 2 व टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। खास तौर पर लखनऊ जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों को लेकर यह बात सामने आई कि आने वाले वर्षों में विकास की यात्रा इन्हीं शहरों से तय होगी। समिट का उद्देश्य वर्तमान जरूरतों और लम्बे समय तक के लक्ष्यों को जोड़ते हुए एक साझा दिशा तय करना रहा। ओमेक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री मोहित गोयल ने कहा कि एनुअल डे और लीडरशिप समिट हमारे लिए केवल समीक्षा का मंच नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। 'एक साथ, एक सपना' हमारी उस सोच को दर्शाता है, जिसमें लखनऊ जैसे शहरों के माध्यम से हम सभी को जोड़ने वाले और टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा फोकस ग्राहक पर केंद्रित विकास और तकनीक आधारित विस्तार पर बना रहेगा। ओमेक्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री जतिन गोयल ने कहा, "आज रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव का नेतृत्व टियर 2 के शहर कर रहे हैं। लखनऊ जैसे शहरों में बढ़ती मांग और भरोसा यह दिखाता है कि भविष्य यहीं आकार ले रहा है। ओमेक्स की प्राथमिकता ऐसे शहरों में भविष्य के लिए जरूरी मूल्य जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स विकसित करना है।" ओमैक्स के बिजनेस हेड अंजनी कुमार पाण्डेय ने कहा, "यह आयोजन लखनऊ के लिए भी खास मायने रखता है। ओमेक्स जिस तरह लखनऊ को अपनी विकास रणनीति का अहम हिस्सा बना रहा है, वह आने वाले समय में यहां के लोगों के जीवन स्तर को नई दिशा देगा। 'एक साथ, एक सपना' केवल एक थीम नहीं, बल्कि लखनऊ सहित सभी उभरते शहरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प है।"

संक्षिप्त खबरें

डीएम का आदेश न मानने पर डीआईओएस ने टाइनी टाट्स को जारी किया नोटिस

अयोध्या।ठंड को देखते हुए डीएम निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा कक्षा एक से लेकर इंटर तक कक्षाओं के संचालन में किए गए परिवर्तन के आदेश को ना मानना टाइनी टाट्स सहादतगंज स्कूल को महंगा पड़ गया।इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने स्कूल के प्रबंधक को 24 दिसंबर तक कारण बताओं नोटिस जारी किया है।इस संबंध में डीआईओएस डॉक्टर पवन तिवारी ने बताया पिछले दिनों जिला अधिकारी के आदेश पर ठंड को देखते हुए उनके तथा बीएसए लाल चंद्र के संयुक्त हस्ताक्षर पर जिले के सभी कक्षा 1 से लेकर इंटर तक के विद्यालयों के संचालन के लिए समय श्रेणी में परिवर्तन किया गया था। बताया कि इसके बावजूद टाइनी टोट्स सहादतगंज स्कूल जिला अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए नहीं पाया गया और समय से पहले स्कूल खुला मिला जिसके चलते स्कूल के प्रबंधक तथा प्रबंधक को 24 दिसंबर तक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। बताया कि अगर इस बीच स्कूल के प्रबंधन तंत्र द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो विभाग द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

कोडीन कफ सिरप केस : आरोपी भोला जायसवाल न्यायिक हिरासत में

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर में कोडीन कफ सिरप मामले के आरोपी भोला जायसवाल को सोमवार को सोनभद्र जेल से लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 5 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ड्रग विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि मामले में कोडीन कफ सिरप की खरीद और बिक्री केवल कागजों में दर्शाई गई थी। जिन फर्मों के नाम पर लेनदेन दिखाया गया, वे सभी फर्जी पाई गईं। उन्होंने यह भी बताया कि दस्तावेजों में जिस ट्रक से सप्लाई दिखाई गई थी, वह वास्तव में ट्रक नहीं बल्कि ऑटो और बाइक का नंबर था। अधिवक्ता ने इस मामले को संगठित तरीके से की गई अवैध गतिविधि बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। सुरक्षा कारणों से दोपहर में भोला जायसवाल को सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका।

सीजेएम कोर्ट की जज श्वेता यादव ने भोला जायसवाल की फाइल को अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन संगीता गौतम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। पुलिस ने शाम लगभग 4रू30 बजे अपर सिविल जज (ए एम 10) संगीता गौतम के समक्ष आरोपी को पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ड्रग विभाग के अधिवक्ता सुभाष चंद्र पांडे ने बताया कि भोला जायसवाल को वारंट श्बीश के तहत सोनभद्र से रिमांड पर लाया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने एबोट कंपनी से कोडीन कफ सिरप खरीदा था, लेकिन उसे कहीं बेचा नहीं था। यह सब केवल कागजों पर हेराफेरी करके किया गया था, जिसमें फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। अधिवक्ता के अनुसार, यह पूरा मामला लगभग 2000 करोड़ रुपये का है। आरोपी को 5 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

रेपर्टवा फेस्टिवल का दूसरा दिन बना कला और आत्मा के संवाद का साक्षी

लखनऊ, (संवाददाता)। जनेश्वर मिश्र पार्क की सर्द हवा में शुक्रवार की शाम कुछ अलग ही रंग लेकर आई। कहीं ठहाकों की गूंज थी, कहीं सूफी प्रेम का संदेश और कहीं शब्दों की गहराती संवेदनाएं। रेपर्टवा फेस्टिवल के दूसरे दिन मंच सिर्फ प्रदर्शन का स्थान नहीं रहा, बल्कि वह एहसासों, विचारों और रचनात्मकता का उत्सव बन गया। शब्द स्टेज पर कवि बादल शर्मा की कविताओं ने माहौल को आत्मीय बना दिया। उनकी रचनाओं में रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे–छोटे दृश्य संवेदना और मुस्कान के साथ बड़े भावों के साथ उभरे। इसके बाद द आहवान प्रोजेक्ट के लोकगीतों ने सुरों के सहारे आत्मचिंतन की राह दिखाई। शाम ढलते ही रंग थियेटर में अभिनेता मानव कौल की संगीतमय दास्तानगोई 'जो डूबा सो पार' ने दर्शकों को भीतर तक छू लिया। निर्देशक अजीतेश गुप्ता और मोहित अग्रवाल की कल्पना में सजा यह हिंदी–फारसी नाटक अमीर खुसरो की जीवन–यात्रा, गुरु निजामुद्दीन औलिया से उनके आध्यात्मिक रिश्ते और सूफी प्रेम के संदेश को जीवंत कर गया। कॉमेडी एरिना में स्टैंडअप कॉमेडियन आकाश गुप्ता ने अपनी तेज–तर्रार टिप्पणियों और आम जिंदगी से जुड़े किस्सों से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। ताल साइलेंट डिस्को स्टेज पर डीजे स्किपस्टर के हिपहॉप और इलेक्ट्रॉनिक मिक्स ने युवाओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। हेडफोन में गूंजती धुनों के साथ नाचते कदम... यह दृश्य खुद में एक आधुनिक कला प्रस्तुति सा लगा। म्यूजिकल एरिना में अनुव जैन की गायकी ने सर्द रात को और भी मुलायम बना दिया। 'बारिश' कार्यक्रम में उनकी आवाज की कोमलता और भावनात्मक गहराई ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने 'इनाम' गाया, तो हर चेहरे पर मुस्कान और तालियों की लय देखने लायक थी। गीतों के बीच उनकी छोटी–छोटी कहानियों ने संगीत को और भी मानवीय बना दिया। वहीं, फेस्टिवल परिसर में फूडजोन, हस्तशिल्प बाजार और बचपन किड्स जोन दिनभर रौनक से भरे रहे।

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के लाभार्थियों के साथ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास विभाग ने आज उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग, गोमती नगर, लखनऊ के प्रेक्षागृह में नन्द बाबा दुग्ध मिशन की योजनाओं के लाभार्थियों एवं प्रगतिशील पशुपालकोंध दुग्ध उत्पादकों के साथ राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, पशुधन एवं दुग्ध विकास, मुकेश कुमार मेश्राम ने की। इस अवसर पर दुग्ध आयुक्तधमिशन निदेशक, प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ, विशेष सचिव पशुधन, विशेष सचिव दुग्ध विकास और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 170 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने नन्द बाबा दुग्ध मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों जैसे बैंक ऋण स्वीकृति में विलम्ब, ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रचार–प्रसार की कमी, व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता और स्वदेशी उन्नत नस्ल के दुधारू गौ–वंश की खरीद में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रमुख सचिव ने लाभार्थियों को आश्वस्त किया कि बैंक ऋण की स्वीकृति में विलम्ब जैसी समस्याओं का समाधान जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर गठित डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स समिति और राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से किया जाएगा। स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय के चयन एवं खरीद हेतु लाभार्थियों को समूहों में विभिन्न प्रदेशों की गौशालाओं में प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट कराए जाएंगे। साथ ही डेयरी इकाई की स्थापना हेतु एनडीआरआई एवं अन्य संस्थानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।दुग्ध आयुक्तधमिशन निदेशक ने मिशन की प्रमुख योजनाओं जैसे नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ–संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लाभ और उनके क्रियान्वयन के प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।प्रबन्ध निदेशक, पीसीडीएफ ने ग्राम स्तर पर दुग्ध समितियों के गठन, संचालन एवं दूध क्रय की पारदर्शिता के बारे में चर्चा की। विशेष सचिव, पशुधन विभाग ने पशुपालकों को दुग्ध उद्यमी के रूप में स्थापित करने हेतु शासन स्तर से सहयोग देने का आश्वासन दिया। निदेशक प्रशासन एवं विकास और अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षण एवं पशुपालन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।संवाद कार्यक्रम के अंत में विशेष सचिव, दुग्ध विकास, राम सहाय यादव ने लाभार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इस प्रकार के संवाद कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने का आश्वासन दिया, ताकि अधिक से अधिक पशुपालकों को योजना से जोड़ा जा सके और उनके सुझावों का समाधान किया जा सके।

जब 20 हजार की नौकरी के लिए अफसरों जैसा साक्षात्कार देना पड़ा

लखनऊ, (संवाददाता)। कमरे में सन्नाटा था। सामने मेज के उस पार बैठे तीन लोग... एक महिला और दो पुरुष। कागजों पर नजर डालते हुए सवाल कर रहे थे। बाहर बैठे युवाओं की आंखों में उम्मीद और चेहरे

पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। यह कोई अफसरों की भर्ती नहीं थी, बल्कि शुक्रवार को अलीगंज राजकीय आईटीआई में आयोजित रोजगार मेला था, जहां तकनीकी पद पर करीब 20 हजार मासिक वेतन की नौकरी के लिए युवाओं को अधिकारी स्तर के साक्षात्कार से गुजरना पड़ा। इस रोजगार मेले में शामिल युवाओं के लिए यह सिर्फ नौकरी का मौका नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की चुनौती भी थी। केवल डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि बोलने का तरीका, आत्मविश्वास, पहनावा और काम की समझ... हर पहलू को परखा जा रहा था। लखनऊ की हेमको ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर जैसे पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। साक्षात्कार हॉल में तीन सदस्यीय पैनल के सामने युवा एक–एक कर पहुंचे। हर अभ्यर्थी को 5 से 10 मिनट मिले। इतने ही समय में उन्हें अपनी पढ़ाई, प्रशिक्षण और भविष्य के सपनों को शब्दों में पिरोना था। सीतापुर से आए उमेश कुमार के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। उन्होंने बताया, एक अधिकारी ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, दूसरे ने प्रशिक्षण और तीसरे ने काम की जानकारी ली। पहनावे और बोलने के तरीके पर भी ध्यान दिया गया। ऐसा लगा जैसे किसी सरकारी अफसर की भर्ती हो रही हो। उन्नाव के प्रवेश यादव जब ईवी वर्ल्ड कंपनी के प्रतिनिधि के सामने बैठे तो सवाल केवल तकनीकी जानकारी तक सीमित नहीं रहे। उनसे देश–दुनिया की घटनाओं और सामान्य ज्ञान पर भी बातचीत हुई। प्रवेश कहते हैं, यह इंटरव्यू मेरे लिए सीखने वाला अनुभव रहा। समझ आया कि नौकरी के लिए जागरूक और आत्मविश्वासी होना कितना जरूरी है। बीपीएल युवाओं के लिए उम्मीद की खिड़की इस रोजगार मेले में खास बात यह रही कि यह आयोजन प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देश पर बीपीएल परिवारों के युवाओं के लिए किया गया था। प्लेसमेंट अधिकारी एम. ए. खान के अनुसार कुल 10 कंपनियों ने भाग लिया ।

केजीएमयू में इलाज के लिए देश विदेश से मरीज आ रहे

लखनऊ, (संवाददाता)। केजीएमयू में देश विदेश से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। यह एशिया का सबसे अधिक बेड वाला संस्थान है। यहां 4250 बेड हैं। प्रतिदिन आठ से 10 हजार मरीज ओपीडी में आ रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में 500 से अधिक मरीज आ रहे हैं। यह जानकारी केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने दी। अटल बिहारी वाजपेई सांइटिफिक कन्वेंशन सेंटर में शनिवार का केजीएमयू का 21 वां दीक्षांत समारोह मना। कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहाकि संस्थान में 62 विभाग चल रहे हैं। जिसमें 53 मेडिकल व नौ डेंटल विभाग हैं। इसमें गायनी आंकोलॉजी व संक्रामक रोग विभाग का संचालन शुरू हुआ है। तीन बैचलर कोर्स संचालित हुए हैं। जिसमें बैचलर ऑफ लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और अप्ट्रोमेट्रिस्ट कोर्स शामिल है। विभिन्न विभागों में डीएम व एमसीएच की 24 सीटें बढ़ी हैं। एम्स जोधपुर, मद्रास आईआईटी, कनाड़ा समेत दूसरे देशों से 14 नए करार हुए हैं। कुलपति ने कहाकि प्रदेश सरकार से केजीएमयू को जरूरत के हिसाब से बजट मिल रहा है। यही वजह है कि केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो सकी।

राज्य महिला आयोग में आजीविका मिशन की कार्यशाला

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में शुक्रवार को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करना और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान के संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहली शर्त जागरूकता है।

मरीज का इलाज पहले,बाकी काम बाद में कहने वाले चिकित्सक महज 24 घंटे में ही अपने ही वादे पर पलटे,कई चिकित्सकों की कुर्सी रही खाली

अयोध्या।जिला चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों के लिए इस ठंड में मरीज का इलाज उतना जरुरी नहीं है। जितना की ज्ञापन देना तथा राजनीति करना इसका उदाहरण सोमवार की सुबह 10रू00 बजे के बाद उसे समय दिखाई दिया।जब जिला चिकित्सालय मे इस ठंड के बावजूद दूरदराज से इलाज कराने आए चिकित्सकों के न रहने के चलते काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और पता करने पर पता चला कि यहां पर तैनात अधिकतर चिकित्सा अपना चिकित्सा

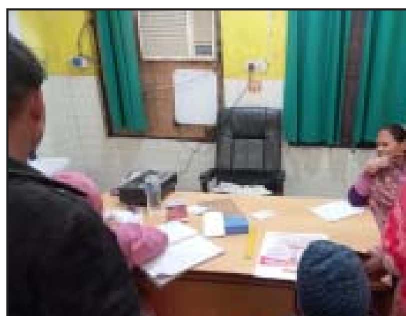

कार्य छोड़कर राजनीति चमकाने के लिए डीएम को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वहीं यहां पर तैनात चिकित्सकों की कुर्सी खाली होने के चलते गंभीर रूप से अलग–अलग रोगों से पीड़ित और खासकर इनके अलावा बच्चे बुजुर्ग मरीज भी बिना इलाज के वापस निजी अस्पतालों की ओर जाना पड़ा।जहां एक ओर रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान निर्मला अस्पताल के प्रबंध तंत्र के निदेशक व चिकित्सक और आई एम ए के पदाधिकारी ने यह कहा कि चिकित्सकों का प्रथम कर्तव्य अपने मरीज का इलाज करना है क्यों ना इसके लिए अन्य सारे काम को छोड़ना पड़े। उसे दिन पत्रकार वार्ता के दौरान ज्ञान परोस रहे निर्मला अस्पताल के डॉक्टर बनौधा ने कहा था कि कोई भी मरीज हो उसे निहस्वार्थ भावना से प्रथम कर्तव्य उसे मरीज का इलाज करना है चाहे क्यों ना इसके लिए अन्य कोई काम छोड़ना पड़े वही ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा था कि हम लोग को पहले अपना मैरिज देखना चाहिए उसके बाद घर परिवार तथा अन्य कामकाज। लेकिन पत्रकार वार्ता के 24 घंटे भी नहीं हुए की यही ज्ञान बांटने वाले निर्मला अस्पताल के निदेशक व चिकित्सा डॉक्टर बनौधा चिकित्सक और आई एम ए के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ना कि केवल सोमवार को ज्ञापन देने के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर कलेक्ट्रेट गए बल्कि अन्य चिकित्सकों को भी अपने साथ ले गए जिसका परिणाम या रहा सोमवार को पूरा दिन चिकित्सा की कुर्सी खाली ही रही और जिसका परिणाम इस ठंड में दूर–दराज से आने वाले मैरिज व उनके परिजनों को भुगत्ता पड़ा कुछ ऐसे गंभीर रूप से मैरिज वहां पर दिखाई दिए जो मजबूरी में जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के न होने पर इधर उधर भटकते रहे और कुछ मैरिज तो इलाज के लिए महंगे और निजी अस्पताल की तरफ रुक किया लेकिन वहां पर भी कई चिकित्सा ज्ञापन देने वाले इन्हीं पदाधिकारी में शामिल रहे और जिसकी नतीजा यही रहा कि सोमवार को कई मरीज का इलाज ना के बराबर ही हुआ।

फर्जी प्रमाण पत्र से होमगार्ड की नौकरी पाने का आरोपी गया जेल

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर। फर्जी जाति प्रमाण–पत्र व अन्य कूटरचित दस्तावेज लगाकर होमगार्ड की नौकरी हथियाने वाले आरोपी अच्छेलाल को गिरफ्तार कर रविवार को अदालत में पेश किया गया। प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट अनुकृति रावत की अदालत ने आरोपी की रिमांड स्वीकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के नई कॉलोनी पुलिस लाइन के रहने वाले वादी पंकज कुमार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी। जिनके आरोप के मुताबिक कूरेभार थाने के राघवपुर–ईरूल के रहने वाले आरोपी अच्छेलाल ने अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज विभाग में देकर होमगार्ड पद पर नौकरी पा लिया था। पंकज कुमार के आरोप के मुताबिक उन्होंने जब इस फर्जीवाड़े की शिकायत विभाग में किया तो मामले की जांच कराई गई और आरोप की पुष्टी होने पर उन्हें 16 अक्टूबर 2023 को होमगार्ड पद से हटा दिया गया। मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तत्कालीन होमगार्ड कमांडेंट राधेरमण सिंह यादव को निर्देशित किया गया था,फिलहाल उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज कराया। प्रकरण के सम्बंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड से भी शिकायत हुई,फिर भी वही हाल रहा। नतीजतन वादी पंकज कुमार को अदालत की शरण लेनी पड़ी। सीजेएम नवनीत सिंह के आदेश के बाद आरोपी अच्छेलाल के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोपी अच्छेलाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया,जिसे अदालत ने जेल भेजने का आदेश दिया है। आरोपी अच्छेलाल की तरह ही उनके भाई रामप्रताप के खिलाफ भी एससी होने के बावजूद एसटी का जाति प्रमाण लगाकर ट्रैफिक पुलिस में एसआई पद पर उन्नाव जिले में नौकरी करने का आरोप लगाते हुए वादी पंकज कुमार ने अर्जी दिया है,जिस पर सीजेएम कोर्ट में बहस के लिए 23 दिसम्बर की तारीख तय की गई है।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ पब्लिक स्कूल,गार्डन सिटी, डीएलएफ में वार्षिकोत्सव "इकोज ऑफ एक्सीलेंस" का भव्य आयोजन

लखनऊ पब्लिक स्कूल, गार्डन सिटी, डीएलएफ शाखा का वार्षिक समारोह "इकोज ऑफ एक्सीलेंस" लखनऊ पब्लिक स्कूल, सेक्टर –9 वृंदावन शाखा में अत्यंत भव्य एवं प्रेरणादायी वातावरण में आयोजित किया गया। यह समारोह विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और

सर्वांगीण विकास को समर्पित रहा। इस अवसर पर विद्यालय की मुख्य प्रशासिका एवं पूर्व एमएलसी कांति सिंह , निदेशक नेहा सिंह एवं गरिमा सिंह तथा प्रधानाचार्या नवनीत कौर की उपस्थिति में यह आयोजन शैक्षिक उत्कृष्टता और संस्कारों का सजीव उदाहरण बना। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए "पल्स ऑफ प्रोविन्सेस" और "तानाजी दृ द अनस्टॉपेबल वॉरियर" जैसी प्रभावशाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं। इन प्रस्तुतियों ने न केवल भारत की विविध संस्कृति और इतिहास को मंच पर जीवंत किया, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, टीमवर्क और अनुशासन को भी दर्शाया।

आग को बुझाने और मानव को बचने के उपाय बताए गए

लखनऊ (प्रत्यूष पाण्डेय).अग्नि आपदा प्रबंधन जनित आपदाओं के अनुकूलन पर क्षमता संवर्ध्दन विषय पर तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सचिव एवं आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बीकेटी में सम्पन्न हुआ। अग्नि आपदा प्रबंधन के तहत छोटी– बड़ी आग पर काबू पाना हेतु प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

जिसमें घर में गैस सिलेंडर, बिजली उपकरण आदि से लगने वाली आग को बुझाने और मानव को बचने के उपाय बताएं गए। स्कूल बिल्डिंग, फैक्टरी में शॉर्ट सर्किट, कैमिकल, लकड़ी आदि का बड़ी मात्र में एकत्रित होने से बड़ी आपदा से बचाया जा सकता है। स्कूल बिल्डिंग में लगी आग के समय बच्चों को सीढ़ियों के माध्यम से बचाव कार्य होना चाहिए जिससे कि जान–माल की क्षति ना हो सकें। प्रशिक्षण के दौरान महानिदेशक ए एल. वेंकटेश्वर लू आईएएस का सम्बोधन हुआ। नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा नामित प्रशिक्षार्थी डिविजनल वार्डेन रमेश सिंह चौहान, डिप्टी डिविजनल वार्डेन रामगोपाल सिंह, वार्डेन अभिनव खंडेलवाल को प्रशिक्षण सम्पन्न अवसर पर आचार्य वरुण चतुर्वेदी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया, अवसर पर डॉ. अरुण, वी.के. सिंह आदि प्रमुख मौजूद रहें।

ग्लोरियस फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में उर्दू और आजादी पर ऐतिहासिक संगोष्ठी का आयोजन

लखनऊ। ग्लोरियस फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वावधान में तथा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सहयोग से 21 दिसंबर 2025, रविवार को एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। ग्लोरियस फाउंडेशन ट्रस्ट की संयोजक नुजहत शहाब चिश्ती ने बताया यह कार्यक्रम "जंगे आजादी में उर्दू जुबान विषय पर केंद्रित है , जिसमें देश की आजादी की लड़ाई में उर्दू भाषा और प्रमुख साहित्यकारों की भूमिका पर गहन विचार–विमर्श होगा । सेमिनार का आयोजन प्रातः 11 बजे नेहरू युवा केंद्र, घंटाघर चौराहे के निकट, लखनऊ में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार इब्राहीम अलवी करेगे । मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध शायर और वरिष्ठ पत्रकार श्री हसन काजमी उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. अब्बास रजा नय्यर, अध्यक्ष, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय अपने विचार रखे रहेंगे । कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्री वी.डी. चौधरी (सहायक आयुक्त, जिला उद्योग, लखनऊ), डॉ. अनीस अंसारी, प्रो. रेशमा परवीन, डॉ. एहतिशाम अहमद खान, श्री वहीदुल्ला अंसारी चतुर्वेदी, श्री परवेज मलिक जादा,

डॉ. नजहत फातिमा तथा श्री हारुन नोमानी शामिल होगे। सभी वक्ता उर्दू भाषा के ऐतिहासिक योगदान और जंगे आजादी के आंदोलन में साहित्यिक संघर्ष की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। सेमिनार का संचालन डॉ. मसीह उद्दीन खान (मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, लखनऊ) करेंगे। "जंगे आजादी का किरदार" विषय के अंतर्गत प्रस्तुत शोधपत्रों ने कार्यक्रम को बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाया है। इस अवसर पर डॉ. परवीन शुजात, डॉ. सीमा सिद्दीकी, डॉ. बुशरा खातून, श्री मुमताज अहमद, श्री राशिद खान, श्री गफरान नसीम, श्री जियाउल्लाह सिद्दीकी, श्री रिजवान अहमद तथा श्री सईद अख्तर आदि लोग अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे। वक्ता इस बात पर बल देंगे कि उर्दू भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रही, बल्कि आजादी की लड़ाई में जनचेतना जगाने का सशक्त हथियार भी बनी। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक और साहित्यिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।

आरपीएफ ने परिजनों से नाराज दो नाबालिक बच्चियों को परिजनों से मिलाया

(राजन तिवारी संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या।कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ निरीक्षक हरीश शाही के तत्परता के चलते परिवार से मां की डांट से नाराज होकर दो नाबालिग किशोरियों को सुरक्षित बरामद किया।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ हरीश शाही ने बताया कि दोनों किशोरियां अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस से दिल्ली जाने की कोशिश कर रही थीं।पूछताछ में सामने आया कि वे दोनों मां की डांट से नाराज होकर बिहार से घर छोड़कर निकल आई थीं।आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें चाइल्ड लाइन को सौंप दिया।बताया यह मामला उस समय सामने आया, जब बिहार के किशनगंज से राजस्थान के अजमेर जा रही अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस अयोध्या कैंट स्टेशन पर रुकी।नियमित जांच के दौरान आरपीएफ कर्मियों को ट्रेन में दो किशोरियां संदिग्ध और लावारिस अवस्था में मिलीं।दोनों की उम्र लगभग 14 और 15 वर्ष बताई गई।संदेह होने पर आरपीएफ ने उनसे पूछताछ की और सुरक्षा में लेते हुए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की।पूछताछ में किशोरियों ने बताया कि वे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के दामू चौक थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं।उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में रहने वाली अपनी एक सहेली से मिलने जा रही थीं, जिसकी हाल ही में शादी हुई है। दोनों बिना किसी को बताए घर से निकल गई थीं।इसके बाद चाइल्ड लाइन को सूचना दी गई। चाइल्ड लाइन ने दोनों किशोरियों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया और फिर उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।समिति ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए किशोरियों की काउंसलिंग कराई और उनके परिजनों से संपर्क किया।परिवार से संपर्क होने पर पता चला कि एक किशोरी की मां ने उसे मोबाइल फोन पर किसी से बात करने से मना किया था और फोन छीन लिया था।इसी बात से नाराज होकर किशोरी ने अपनी सहेली के साथ दिल्ली भागने की योजना बनाई थी। दोनों परिवारों ने बेटियों के लापता होने की जानकारी न मिलने पर काफी चिंता जताई थी।

सीओ सदर ने सर्किल के तीनों थाना प्रभारियों के साथ किया पैदल गस्त

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।रविवार की शाम कोहरे व ठंड को देखते हुए सड़क हादसे से बचने के लिये सीओ सदर अरविन्द सोनकर ने थानाध्यक्ष रौनाही, महाराजगंज व गोशाईगंज के साथ पैदल गस्त किया। इस दौरान उन्होंने इन थाना क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों,मार्गो तथा गलियों में पुलिस कर्मियों के साथ पैदल गस्त किया।पैदल गस्त के दौरान उन्होंने लखनऊ गोरखपुर व हाईवे के अलावा अम्बेडकर नगर राष्ट्रीय मार्ग पर आने जाने वाले भारी वाहनों जिसमें ट्रैक्टर ट्राली,ट्रक, डीसीएम, टैक्सी के अलावा ऐसे वाहन जिस पर रिफलेक्टर तथा फाग लाइट नहीं लगी हुई थी।उनके वाहन चालकों से कहा कि आने वाले दिनों में शीत लहरी तथा कोहरे को देखते हुए सभी लोग इसका प्रयोग करें क्योंकि अधिकतर दुर्घटना से गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहनों तथा सामने से आ रहे वाहनों के न दिखाई पडने के चलते हो रही है।इसके अलावा इन पुलिस अधिकारियों ने पैदल ग्रस्त करते हुए स्थानीय लोगों से अपील किया

कि वे सभी संदिग्ध रूप में दिखाई देने वाले लोगों के बारे में बेहिचक स्थानीय पुलिस थानों तथा पुलिस चौकिया पर जाकर कह सकते हैं जिससे कि समय रहते किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। इस मौके पर इन पुलिस अधिकारियों ने वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कई वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही भी किया।

संक्षिप्त खबरें

शैली ट्रेडर्स समेत जौनपुर में दर्ज 12 मुकदमों से जुड़ी याचिका को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में शासन के निर्देशों की धज्जी उड़ाने वाले प्रतिबंधित कोडिंन कफ सिरप कांड से जुड़े नशे के सभी 12 सौदागरों कि याचिका उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निरस्त कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा पूर्व में शैली ट्रेडर्स व जनपद के 12 अन्य मेडिकल प्रतिष्ठानों पर दर्ज की गई एफआईआर प्रकरण में घटना से जुड़े आरोपितों को किसी भी प्रकार की राहत देने से साफ इनकार कर दिया। उधर उच्च न्यायालय में नशे के सौदागरों की याचिका

रद्द होने से प्रदेश की आयुक्त रोशन जैनब ने खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ने भी इस कार्रवाई पर बड़ी शाबासी दी है। प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बिंदु बने कोडीन कफ सिरप के इस बहुचर्चित मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जौनपुर के सभी 12 आरोपितों द्वारा अपने बचाव के लिए दर्ज मुकदमे से संबंधित एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर बेहद ही गंभीरता से सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने सभी को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा आरोपितों की याचिका को खारिज किए जाने से यह साफ हो गया कि जौनपुर के जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय द्वारा की गई कार्रवाई मिल का पत्थर साबित हो रही है। इस संबंध में बात करते हुए जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडेय ने बताया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का यह न्याय जनहित में एक स्तंभ के रूप में दिया गया है। अब औषधि के गलत तरीके से व्यापार करने वाले , कोडिन युक्त कफ सिरप एव अन्य एनआरएक्स श्रेडी की औषधियों की गैरकानूनी व्यापार में शामिल लोगों को डर रहेगा। औषधि निरीक्षक द्वारा यह भी बताया गया की दिल्ली स्थित संचालित फर्म एस वी ट्रेडर्स परपतगंज, दिल्ली के संचालक शादाब पुत्र रियाज निवासी गाजियाबाद द्वारा लगभग 48 हजार कोडिन युक्त एस्कुफ कफ सिरप की अवैध रूप से बिक्री विशेसरगंज जौनपुर स्थित फर्म मनीष मेडिकल एजेंसी को हुई है। जबकी अर्जुन सोनकर पुत्र प्रेमचन्द्र सोनकर की फर्म मनीष मेडिकल एजेंसी जांच के दौरान मौके पर संचालित ही नहीं हो रही है। इनके द्वारा सप्लाई की गई कफ सिरप की अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये आकी गई है। जिले के एएसपी गोल्डी गुप्ता के निर्देश पर पूर्व में दर्ज की गई एफआईआर में समयोजित कर प्रकरण की विवेचना एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

नए युग के अचीवर्स के लिए 'लिव अप सक्सेस' की नई ब्रांड फिल सफी पेश

लखनऊ। भारत में युवाओं पर केंद्रित सबसे तेजी से विकसित होते हुए व्हिस्की ब्रांड, रॉयल ग्रीन व्हिस्की की फिलॉसफी "टेस्ट द सक्सेस" से "लिव अप सक्सेस" में बदल गई है। साहसी और नई फिलॉसफी "लिव अप सक्सेस" जेन जी और मिलेनियल्स के बदलते दृष्टिकोण के अनुरूप रॉयल ग्रीन व्हिस्की की नई पोजिशनिंग है। यह पीढ़ी सफलता को न केवल एक पड़ाव, बल्कि दैनिक लम्हों, छोटी–छोटी कामयाबियों और व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में देखती है। एडीएस स्पिरिट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, पारस मान ने कहा, "हमारी रिपोजिशनिंग केवल हमारी टैगलाईन को नहीं बदल रही है, बल्कि हम नई पीढ़ी के सामने खुद को कैसे रखते हैं, इसमें परिवर्तन लेकर आ रही है। आज सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग है, जो व्यक्तिगत है, अस्त–व्यस्त है, और लगातार आगे बढ़ता हुआ है। यह पहचानकर हमने 'लिव अप सक्सेस' की टैगलाईन दी है। यह व्यस्तता, असफल हुई मेहनत और छोटी–छोटी सफलताओं को सम्मानित करती है, जो बहुत मायने रखती हैं। 'लाईव अप सक्सेस' के साथ हम न केवल बड़ी उपलब्धियों, बल्कि कोशिश करते रहने के साहस, लगातार आगे बढ़ते रहने की लगन और कुछ उपयोगी कर दिखाने की खुशी का जश्न भी मना रहे हैं। रॉयल ग्रीन व्हिस्की इन विश्वसनीय और दैनिक खुशियों के लिए आपकी सबसे अच्छी साथी है।" आज के युवा ग्राहक अपनी महत्वाकांक्षा को नए सिरे से लिख रहे हैं। वो देर रात तक एडिटिंग करते हैं। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट संभालते हैं और रचनात्मक सहयोग करते हैं। वो व्यक्तिगत विकास की ओर बढ़ते हुए उसे प्रदर्शित करने का साहस रखते हैं। 'लिव अप सक्सेस' इन्हीं छोटी–छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीतों की खुशी मनाती है, उनकी भागदौड़, पहचान और सफर को परिभाषित करती है और रॉयल ग्रीन को इन प्रामाणिक खुशियों की एक महत्वपूर्ण साथी बनाती है। "लिवअप सक्सेस" अभियान एक नई डायनामिक ब्रांड डिजिटल फिल्म के साथ चलाया जा रहा है, जिसमें आज के अचीवर्स की मेहनतकश और शुद्ध गति प्रदर्शित की गई है। यह फिल्म दर्शकों को सीधे एक्शन में ले जाती है, जिसमें देर रात एडिट, क्रिएटिव ब्रेकथ्रू, शंकाओं के पल, साथ में मिलकर काम करना, और बैक अप रखने का आत्मविश्वास शामिल है। फिल्म के तेज कट, जीवंत विज्युअल, और प्रामाणिक किरदार सफलता को छोटी–छोटी व्यक्तिगत उपलब्धियों के रूप में दिखाते हैं, जो समय के साथ मिलती चली जाती हैं। रॉयल ग्रीन न केवल बड़ी सफलताओं, बल्कि इन छोटी–छोटी उपलब्धियों की भी एक महत्वपूर्ण साथी है। यह फिल्म युवा दर्शकों को एक स्पष्ट संदेश देती है: आप सफलता के पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप सफलताओं के साथ जी रहे हैं, और एक–एक करके उन्हें प्राप्त करते जा रहे हैं। "लिव अप सक्सेस" अभियान एक इंटीग्रेटेड ब्रांड परिवेश, जैसे रील्स, क्रिएटर निर्मित स्टोरीटैलिंग, शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स, संस्कृति से जुड़े सहयोगों और रिटेल विजिबिलिटी के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जो युवा भारतीयों की आवाजों और उनके जीवन की वास्तविकताओं को सामने लाएगा।

एसटीएफ मुठभेड़ में एक लाख का इनामी सिराज अहमद ढेर

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुलतानपुर/ सहारनपुर। सुलतानपुर के बहुचर्चित दिवानी

न्यायालय अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में वांछित और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश सिराज अहमद का अंत हो गया। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल सिराज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुठभेड़ गंगोह थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई।एसटीएफ को सूचना मिली थी कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में पंजाबदृ हरियाणा बॉर्डर से होकर सहारनपुर पहुंचा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम ने गंगोह क्षेत्र में घेराबंदी की। खुद को घिरता देख सिराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया,जहां उसकी मौत हो गई।गौरतलब है कि 8 अगस्त 2023 की शाम सुलतानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आजाद अहमद की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में हत्या का मुख्य आरोपी सिराज अहमद सामने आया था,जो तभी से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी न होने पर उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और उसकी तलाश में एसटीएफ को लगाया गया था।फरारी के दौरान मार्च 2025 में न्यायालय के आदेश पर सिराज की करोड़ों रुपये की चल–अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं। इसके बावजूद वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय बना हुआ था।मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ ने एक मोटरसाइकिल, दो पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, चार मोबाइल फोन, दो वाई–फाई डोंगल, एक छोटा बैग और आधार कार्ड समेत अन्य कागजात बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार सिराज अहमद का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हत्या, हत्या के प्रयास और रासुका जैसी गंभीर धाराओं में करीब 30 मुकदमे दर्ज थे।इस संबंध में कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि सहारनपुर में मुठभेड़ के दौरान सिराज के घायल होने और बाद में मौत की पुष्टि हुई है। उसका आपराधिक इतिहास पहले ही एसटीएफ के साथ साझा किया जा चुका था। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।